>

Title: Need for equitable distribution of power in the country.

श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी (अहमदनगर): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। बिजली देश की जीवन रेखा है। इसका फेल होना नुकसान तो पहुंचाता है, साथ ही भारी पीड़ादायक और देश के लिए अपमानजनक भी है। हमने निर्धारित बिजली उत्पादन का लक्ष्य आधा ही हासिल किया है। बिजली की मांग कितनी है, इस महत्वपूर्ण तथ्य का आकलन करने पर जानकारी मिलती है कि उद्योग विभाग में 35 प्रतिशत की मांग है, कृषि में 28 प्रतिशत की मांग है, 28 प्रतिशत की मांग घरेलू उपयोग के लिए है और नौ प्रतिशत व्यावसायिक कार्यों के लिए उपयोग होती है। हर बार बिजली का बढ़ता उत्पादन उन लोगों के काम आता है, जो इसे खरीदने की क्षमता रखते हैं। इसमें कृषि क्षेत्र पिछड़ जाता है और गैर उत्पादन कार्यों के लिए उपयोग बढ़ाता जा रहा है। इसके अलावा ताकतवर राज्यों द्वारा अपने कोटे से ज्यादा बिजली खींची जाती है। इसी वजह से पावरग्रिड फेल हो जाता है और देश की छवि को गहरा धक्का लगता है। वास्तविक बिजली उत्पादन की प्राकृतिक सीमाएं हैं, इससे ज्यादा उत्पादन नहीं हो सकता, इस तथ्य को ध्यान में रखकर हर राज्य को जितना कोटा दिया जाता है, वह उतनी ही बिजली निकालें, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर उन राज्यों को ज्यादा बिजली की आवश्यकता हो तो सौर ऊर्जा सहित सारी ऊर्जा का उपयोग करने के लिए सरकार द्वारा उचित कदम उठाने चाहिए। महाराष्ट्र में परली के सभी ऊर्जा संयंत्र पानी न होने के कारण बंद पड़े हैं। अकाल की परिस्थिति गंभीर बनी हुई है। बच्चों की परीक्षा के दिन होने के नाते बिजली की बहुत ही आवश्यकता है। पॉवर ग्रिड से महाराष्ट्र को ज्यादा से ज्यादा बिजली दें और मेरा चुनाव क्षेत्र सबसे ज्यादा सूखा प्रभावित क्षेत्र होने के कारण मैं सरकार से प्रार्थना करता हूँ कि वे ज्यादा से ज्यादा बिजली दें।